

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना संख्या-138 / 2024  
(अपील संख्या :-6106 / 2022)

यतीश सरण

—अपीलार्थी / प्रार्थी

## बनाम

1. डॉ. समित शर्मा, शासन सचिव, भू-जल विभाग एवं पीएचईडी, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्री सतीश कुमार गर्ग, शासन उप सचिव, भू-जल विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. श्री सुरज भान, मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना निदेशक, अटल भूजल योजना, भू-जल विभाग, जोधपुर।

—अप्रार्थीगण / प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 04.05.2024  
विनिश्चय की दिनांक : 26.11.2024

## उपस्थित :

प्रार्थिया की ओर से : श्री अरविन्द राणा, अभिभाषक।  
अप्रार्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक।

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य  
चेतन राम देवडा, सदस्य

## आदेश

1. प्रार्थी/अपीलार्थी ने यह अवमानना याचिका इस अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपील संख्या 6106/2022 में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2023 की पालना नहीं करने व अधिकरण के आदेश की जानबूझ कर अवमानना करना बताते हुए दिनांक 04.05.2024 को इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की है। अधिकरण द्वारा दिनांक 09.05.2023 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया था :-

“उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि यदि अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 1990-91 के विरुद्ध सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य पाया जाता है, तो उसके संबंध में रिव्यू डी.पी.सी. आयोजित कर उक्त पद पर पदोन्नति हेतु उसके नाम पर विचार किया जावे और यदि अपीलार्थी उक्त पद पर पदोन्नति हेतु योग्य पाया जाता है तो उसे नियमानुसार

*समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।”*

2. प्रार्थी द्वारा कहा गया है कि उसने निर्णय की पालना हेतु दिनांक 08.05.2024 को प्रत्यर्थागण के समक्ष जरिये अधिवक्ता विधिक नोटिस प्रस्तुत किया, जिसकी फोटो प्रति अनुलग्नक-5 है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण ने निर्णय की पालना जानबूझ कर नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध अधिकरण के आदेश दिनांक 09.05.2023 की पालना नहीं किये जाने के कारण अवमानना प्रकरण बनाकर माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जावे।
3. इस अवमानना आवेदन की पालना करने हेतु दिनांक 27.08.2024 को प्रत्यर्थागण को नोटिस जारी किए गए थे तथा दिनांक 17.09.2024 एवं 15.10.2024 को राजकीय अधिवक्ता को पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के भी निर्देश जारी किए गए थे।
4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अपीलार्थी के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में कहीं भी प्रतिकूल प्रविष्टि का इन्द्राज नहीं किया गया है, जिस कारण से अपीलार्थी को सूचित नहीं किया गया है। यदि प्रतिकूल प्रविष्टि का इन्द्राज होता है, तो सूचित किये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी के वर्ष 1990-91 से पूर्व के 07 वर्षों के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में सन्तोषजनक तथा अच्छा ही अंकित किया हुआ था, जबकि इनसे कनिष्ठ कार्मिक एन.के. दत्ता के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में उत्कृष्ट तथा बहुत अच्छा अंकित किया हुआ होने से एन.के. दत्ता को पदोन्नति के लिए योग्य पाया तथा अपीलार्थी को योग्य नहीं पाया। अतः अपीलार्थी द्वारा उक्त अवमानना प्रार्थना पत्र को निरस्त/ड्रॉप करने का निवेदन किया। अधिकरण के आदेश के अनुसरण में रिव्यू डीपीसी आयोजित करने के संबंध में कोई तथ्य जवाब में अंकित नहीं किए गये हैं।
5. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया।
6. यह अवमानना याचिका दिनांक 04.05.2024 को पेश की गयी थी। उसके बाद दिनांक 27.08.2024, 17.09.2024 एवं 15.10.2024 की तिथियां अप्रार्थीगण को आदेश की पालना के लिये दी गयी थी, परन्तु अप्रार्थी विभाग ने आदेश दिनांक 09.05.2023 की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि

अधिकरण के द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना प्रत्यर्थागण/अप्रार्थागण ने अभी तक नहीं की है। अतः अप्रार्थागण-प्रत्यर्थागण के लिये यह आवश्यक था कि वे अधिकरण के आदेश की समयावधि में पालना करते या माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्रियान्विति पर कोई स्थगन आदेश प्राप्त करते। प्रिवी काउन्सिल के सर लॉरेन्स जेनकिन्स ने जसकर्ण बोइद बनाम पिरथीचन्द लाल (ए.आई.आर. 1918 पी.सी. 151) के प्रकरण में निम्न प्रकार अवधारित किया था :-

*"whatever be the theory under other systems of law, under the Indian law and procedure an original decree is not suspended by the presentation of an appeal nor is its operation interrupted where the decree on appeal is merely one of dismissal. There is nothing in the Indian law to warrant the suggestion that the decree or order of the court or tribunal of the first instance becomes final only on the termination of all proceedings by way of appeal or revision."*

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह (ए.आई. आर. 1958 एस.सी. 86) में प्रिवी कौंसिल के पूर्वोक्त निर्णय का अनुमोदन करते हुए निम्न मत व्यक्त किया था :-

*"the filing of an appeal might put the decree or order in jeopardy but until it is reversed or modified it remains effective."*

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी.डी.देसाई ने हंसराज धीर के प्रकरण (1985 Cri. L.J. 1030) में अवमानना प्रकरण के सिद्धान्तों की निम्न प्रकार व्याख्या की थी :-

*"Once a case is decided, it is the bounden duty of the State and its subordinates to implement, with the utmost expedition, the said decision. In a Government which is ruled by law, there must be complete awareness to carry out faithfully and honestly the decisions rendered by courts of law after effective adjudication. Then only will private individuals, organisations and institutions learn to respect the decisions of courts. In absence of such attitude on the part of all concerned, chaotic conditions might arise and the functions assigned to the courts of law under the Constitution might be rendered a futile exercise. It requires to be emphasised, in this connection, that mere preferment of an appeal does not automatically operate as a stay of the decision under appeal and that till an application for stay is moved and granted by the appellate court, or, in the alternative, the court which rendered the decision is moved and grants an interim stay of the decision pending the preferment of an appeal and grant of stay by the appellate court, the decision continues to be operative. Indeed, non-compliance with the decision on the mere ground that an appeal is contemplated to be preferred or is actually preferred, and that, therefore, the matter is subjudice, may amount to contempt of court punishable under the Contempt of Courts Act, 1971."*

- उपर्युक्त विनिश्चयों के आलोक में और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विनम्र मतानुसार यह स्पष्ट है कि अप्रार्था-प्रत्यर्थागण ने इस अधिकरण के आदेश दिनांक 09.05.2023 की पालना न कर उक्त न्यायिक

आदेश की अवमानना कारित की है। हम इस अवमानना प्रकरण को अधिकरण में लम्बित रखना उचित नहीं समझते हैं और इस प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 10 के प्रावधान के क्रम में उपर्युक्त अवमानना कृत्य के लिए अवमाननाकर्ताओं के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु संदर्भित करना उचित समझते हैं।

8. परिणामस्वरूप प्रार्थी-अपीलार्थी की अवमानना याचिका स्वीकार की जाकर इस अधिकरण के रजिस्ट्रार को निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस संदर्भ में अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम-1971 की धारा 10 के अन्तर्गत अवमानना की कार्रवाई के विचाराणार्थ प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर को संदर्भित करावें।

(चेतन राम देवडा)  
सदस्य

(शुचि शर्मा)  
सदस्य